www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 145 नागपुर, शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

चुनाव आयोग को मिलेंगी 30,000 नई वीवीपैट मशीनें

नई दिल्ली

निर्वाचन आयोग को इस जुलाई में 30,000 नई कागज रसीद निकालने वाली इलेक्ट्रानिक वोटिंग यानी वीवीपैट मशीनें मिल जाएंगी। इसके बाद आयोग के पास इन मशीनों की इतनी संख्या हो जाएगी, जिससे वह इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर इनका इस्तेमाल कर सकेगा।

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया, वर्तमान में हमारे पास करीब 53,000 वीवीपैट (वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीनें हैं। अगले तीन महीनों में हमें 30,000 नई वीवीपैट मशीनें मिल जाएंगी। गुजरात और हिमाचल में सभी मतदान केंद्रों में इस्तेमाल के लिए करीब 84,000 मशीनें पर्याप्त होंगी। हालांकि विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के एलान के दौरान ही आयोग इन दोनों राज्यों में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीनों के प्रयोग करने की आधिकारिक घोषणा करेगा। वैसे गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 जनवरी को समाप्त होगा। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल भी अगले वर्ष सात जनवरी को पूरा होगा। इसको देखते हुए इन दोनों प्रदेशों में इस साल दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं।

जाकिर नाइक पर शिकंजा कसा, एनआइए ने जारी किया गैर जमानती वारंट

मुंबई

एनआइए की विशेष अदालत ने विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। आतंकवादी मामले में कथित भूमिका के लिए एजेंसी को इस्लाम धर्म के प्रचारक की तलाश है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने नाइक के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत पिछले वर्ष मुकदमा दर्ज किया था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि तीन समन जारी करने के बाद भी नाइक उसके सामने हाजिर नहीं हुए। उन्हें भारत लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। विशेष अदालत के न्यायाधीश वीवी पाटिल ने नाइक के खिलाफ गैरजमानती जारी किया।

पिछले सप्ताह मुंबई की एक अन्य अदालत से भी नाइक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जा चुका है। यह वारंट मनी लांड्रिंग मामले में वारंट जारी किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने नाइक के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामला दर्ज किया है। निदेशालय के वकील ने कहा था कि नाइक संभवत: संयुक्त अरब अमीरात में छिपे हैं। 51 वर्षीय नाइक पिछले वर्ष से फरार चल रहे हैं।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकवादी हमले में शामिल कुछ आतंकियों ने उनसे प्रभावित होने का दावा किया था। ढाका हमले के बाद एनआइए ने नाइक और उनके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सभी के खिलाफ भादवि की धारा 153-ए (विभिन्न समुदायों के बीच धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

राजनाथ सिंह की नौकरशाहों को नसीहत, नेताओं के 'यसमैन' न बनें

नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नौकरशाह नेताओं के 'यसमैन' न बनें। अगर वह कोई गलत काम कराने के लिए दबाव डालते हैं तो नियमों का हवाला देकर उन्हें स्पष्ट शब्दों में न कह दें। सिविल सर्विस डे पर आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र आन-बान-शान से कायम है तो इसका श्रेय नौकरशाहों को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी को न केवल भेदभाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए बल्कि राष्ट्रहित में कोई कड़ा फैसला लेना पड़े तो उससे बिलकुल न पीछे हटें।

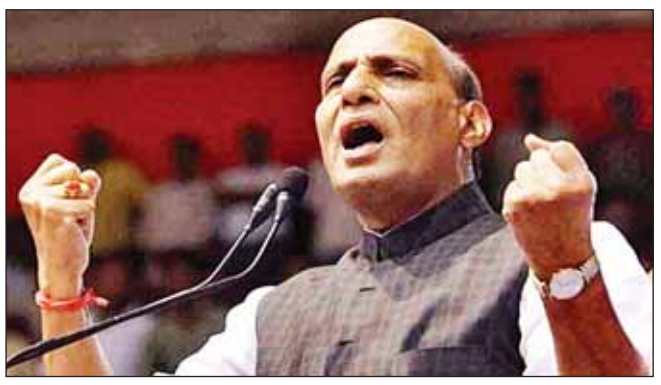

समाज में बदलाव लाने के लिए आइएएस व समकक्ष अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास ताकत है, लेकिन वह इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिम्मेदारी, जवाबदेही इसी ताकत के साथ आती हैं। तीसरी अहम चीज है भेदभाव पूर्ण रवैया। अगर यह गुण अधिकारी में नहीं है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई निर्णय लेने में परेशानी आती है तो अपने वरिष्ठों से विचार विमर्श करने में पीछे नहीं हटे, लेकिन फैसला हर हाल में होना चाहिए।

मोदी सरकार अंत्योदय योजना को लागू करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने नौकरशाहों से आह्वान किया कि गरीबों को अन्न मुहैया कराने के इस नेक काम को सिरे चढ़ाने में अपना बेहतरीन योगदान दें। प्रधानमंत्री का सपना है कि सरकार 2022 तक सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दे। अधिकारी सुनिश्चित करें कि यह सपना हकीकत में बदले। राजनाथ बोले कि देश के पहले गृहमंत्री सरकार वल्लभभाई पटेल ने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

2 साल में बुंदेलखंड की पानी की किल्लत दूर कर देंगे - योगी

बुंदेलखंड

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड की पानी की समस्या 2 साल में खत्म करने का आश्वासन दिया। बतौर मुख्यमंत्री वह गुरुवार को अपने पहले बुंदेलखंड दौरे पर झांसी में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुंदेलखंड के लिये अप्रूव की गईं सभी योजनाएं लागू करके अगले 2 साल में सूखे से त्रस्त बुंदेलखंड की पानी की समस्या पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान यह भी किया कि बुंदेलखंड को नई दिल्ली से सिक्स-लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा।

योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को सीधे दिल्ली से जोड़ने का मतलब है कि यहां आने वाले 5 सालों में कई नये उद्योग लगेंगे, जिनसे यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र से पलायन रुकेगा। हम विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। 24 घंटे बिजली, हर गरीब के सिर पर छत और हर घर में शौचालय दे पाएंगे। हमें बस आपका सहयोग चाहिये।

मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपने बनाई और हम काम करना चाहते हैं। हमारे मंत्री 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में तो 1 घंटे भी काम नहीं करते थे। आपको सरकार की योजनाओं में कहीं भी, कभी भी कोई कोई खामी दिखे तो उसकी सूचना जन प्रतिनिधि तक पहुंचाएं।

उन्होंने कहा कि किसी को अवसर मत दीजिये, कानून को हाथ में मत लीजिये। कानून का काम करने वाले लोग खुद काम करेंगे। आप बस अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिये या संबंधित अधिकारी को बता दीजिये। प्रदेश की अपेक्षाओं पर सरकार पूरी तरह खरी उतरेगी। साथ ही योगी ने अधिकारियों से कहा कि वे 3 दिन के अंदर शिकायतो का निस्तारण करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले उन्हें समझाया जाएगा और फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

योगी ने एक और भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं अभी तो कमिश्नरी स्तर के कार्यक्रम में आया हूं, लेकिन आप विश्वास कीजिये कि मैं जिला स्तर के कार्यक्रमों में भी आऊंगा। यहां मैं यह बताने आया हूं कि अब सरकार बदल चुकी है, अब कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अब जनता के प्रति संवदेनशील सरकार है तो प्रशासन को भी संवेदनशील बनना होगा। इस अवसर पर योगी ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला और जनधन जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब किसी गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का चूल्हा जलता है वही अच्छे दिन की शुरुआत है। जब किसी गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन निशुल्क लगता है वही अच्छे दिन की शुरुआत है।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

ड्रैगन को भारत का जवाब, नाम बदलने से चीन का नहीं हो जाएगा अरुणाचल

नई दिल्ली

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र का नाम बदल देने से अवैध रूप से नहीं हथिया सकते। उन्होंने चीन को आगाह करते हुए ये बात कही।

बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के अरुणाचल दौरे से चिढ़कर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह जगहों का नाम बदलकर अपना हिस्सा दिखाया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 14 अप्रैल को नए नामों की घोषणा की। चीनी, तिब्बती और रोमन वर्णों में इन जगहों के नाम कैसे लिखे जाएंगे इसका मानक भी तय कर दिया गया है। इन छह जगहों का नाम वोग्यैनलिंग, मिला री, क्वाइदेनगाबरे री, मेनक्यूका, बूमो ला और नामाकापुब री रखा गया है।

अखबार ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि यह कदम विवादित क्षेत्र में देश की क्षेत्रीय संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बीजिंग की मिंजू यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के प्रोफेसर जियोंग कुनजिन के हवाले से कहा गया है,

■ शेष पृष्ठ 2 पर

कश्मीरी को गाड़ी से बांधने के मामले में सेना ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

नई दिल्ली

कश्मीर में भारतीय सेना की ओर से कथित रूप से एक कश्मीरी युवक को जीप पर बांधने के मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कश्मीरी युवक सेना की गाड़ी के आगे बंधा हुआ था। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था। इस ट्वीट से पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के ज़रिए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक शख़्स को आर्मी जीप के बंपर पर बंधा हुआ देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सेना ने मामले में जांच की बात कही थी।

बरखा सिंह ने कांग्रेस की महिला इकाई से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली

अरविंदर सिंह लवली के बाद कांग्रेस को जोरदार झटका देते हुए दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह ने गुरुवार को पार्टी की महिला शाखा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के लिए उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि वे मानते हैं कि राहुल पार्टी को लीड करने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं हैं।

बरखा सिंह ने कहा, राहुल गांधी और अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तीकरण तथा महिला सुरक्षा मुद्दों का इस्तेमाल केवल वोट लेने के लिए किया। उन्होंने कहा, मुद्दे से उनका कोई लेना-देना नहीं है। सिंह ने कहा, मौजूदा संगठन में जब मैं खुद असुरक्षित थी, फिर उस संगठन में रहकर मैं महिलाओं को कैसे सशक्त कर सकती थी। इसलिए मैंने दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

राहुल पर लगाए गंभीर आरोप

बरखा ने आगे कहा, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि राहुल गांधी पार्टी को लीड करने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं है, लेकिन वे ऐसा कहते नहीं, इसकी वजह मैं नहीं जानती। बरखा ने कहा, राहुल गांधी संगठन में मौजूद मुद्दों का समाधान करने के अनिच्छुक हैं। राहुल गांधी क्यों उन नेताओं की बैठक नहीं लेना चाहते, जो उनसे सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा, वह केवल चाटुकारों की बैठक लेने के इच्छुक हैं, उन नेताओं के नहीं, जो सवाल पूछते हैं।

खुद को कांग्रेस का वफादार सिपाही करार देते हुए उन्होंने कहा कि वह आगे भी पार्टी की वफादार रहेंगी।

कुलभूषण पर पाक नहीं दे रहा है सही जवाब, भारत ने 15वीं बार रखी मिलने की मांग

नई दिल्ली

भारत सरकार ने पाकिस्तान से अधिकारिक तौर पर यह बताने को कहा है कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ कौन-सी न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई, उनके खिलाफ मुकदमा किस तरह से चला और उन्हें किस तरह से सजा सुनाई गई। कुलभूषण जाधव से भारत के प्रतिनिधि को मिलने देने के लिए अब तक विदेश मंत्रालय की तरफ से 15 बार पाकिस्तान को अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है।

बुधवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को बुलाकर कुलभूषण जाधव के खिलाफ सभी तथाकथित सबूत और उससे संबंधित दस्तावेज मांगे गए। पाकिस्तान से यह भी पूछा गया है कि वह लिखित तौर पर यह बताए कि वहां की एक मिलिटरी कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान सरकार उनके बारे में आगे क्या करने को सोच रही है।

कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है उसकी कॉपी की भी मांग की गई। भारत ने बार-बार यह बात कही है कि अगर कुलभूषण जाधव को कुछ होता है तो भारत इसे सोची-समझी हत्या करार देगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने गुरुवार को बताया कि पाकिस्तान को यह बात साफ तौर पर बता दी गई है की कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। वह पूरी तरह निर्दोष हैं और उनका अपहरण करके उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है। भारत कुलभूषण जाधव को रिहा कराने के लिए हर तरह के प्रयास जारी रखेगा।

हालांकि, उन्होंने इस बात को माना कि कुलभूषण जाधव कहां हैं और किस हालत में हैं, इस बारे में पूछे जाने पर भी पाकिस्तान ने कोई जानकारी नहीं दी है। पाकिस्तान सिर्फ इतना ही बता रहा है की कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की हिरासत में हैं। भारत ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि कुलभूषण जाधव किस हालत में हैं और उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब यह पूछा गया कि कुलभूषण जाधव को बचाने के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, तो सरकार उस पर क्या जवाब देगी। इस पर गोपाल बागले का कहना था कि इस बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि कुलभूषण जाधव को बचाने के बारे में भारत सरकार हर प्रयास कर रही है।

सोनिया से मिले नीतीश कुमार, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को लेकर हुई बात

नई दिल्ली

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से गुरूवार को उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस भेंट में उन दोनों के बीच देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार लगातार राष्ट्रीय स्तर पर 2015 के विधान सभा चुनाव की तरह ही धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच एक बड़े ग्रांड अलायंस (बिहार में बने महागठबंधन जैसा) बनाने की पैरवी करते आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात में यह मुद्दा भी उठा होगा। बिहार में महागठबंधन के बैनर तले विधान सभा चुनाव जीतने के बाद राज्य की सत्ता में नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ लालू की आरजेडी और कांग्रेस की साझा सरकार है।

कश्मीर हालात पर बढ़ी पीएम मोदी की चिंता, केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

नई दिल्ली

कश्मीर घाटी में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। घाटी में बढ़ती हिंसा और तनाव ने केंद्र सरकार के माथे पर बल ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कश्मीर को लेकर चिंता में हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक के फौरन बाद उन्होंने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। इस बैठक में कश्मीर चर्चा का केंद्र रहा। करीब तीन घंटे तक चली बैठक में जम्मू से पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे।

इनके अलावा रक्षा और वित्तमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वैंकेया नायडू और पार्टी महामंत्री रामलाल भी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री को राज्य के ताजा हालात से रू-ब-रू कराया गया। पिछले हफ्ते घाटी के दौरे पर गए सेना प्रमुख का आकलन, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से उनकी बातचीत और खुफिया विभाग की रिपोर्ट से पीएम को अवगत कराया गया। सरकार की कोशिश हालात को काबू करने की रहेगी, अगर ऐसा जल्द नहीं हुआ तो मुमकिन है केंद्र सरकार कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला ले ले। सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के रवैये से सेना में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती के स्टैंड से भाजपा भी खफा है।

तो क्या राष्ट्रपति शासन विकल्प है

भाजपा की राज्य इकाई लगातार महबूबा मुफ्ती के बर्ताव और काम करने के तरीके को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करती रही है। अब हालात बेकाबू होता देख भाजपा नेतृत्व पीडीपी को सख्त रवैया दिखाने के मूड में है। नेताओं का मानना है कि कश्मीर में तनाव ने मोदी की छवि को कमजोर करने का काम किया है।

अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्य में सत्ता सुख की आस ने मोदी के हाथ बांध रखे हैं? इन सवालों के बीच ही अब इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि राज्य में महबूबा से नाता तोड़कर राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ा जाए। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती की कोशिश उपचुनाव में अपने भाई को जिताकर केंद्र की राजनीति में पहुंचाने की थी। मुफ्ती चाहती थीं कि वो एनडीए का हिस्सा बनकर भविष्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में अपने भाई को जगह दिलाएं हालांकि उपचुनाव में भाई की हार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल महबूबा मुफ्ती 23 तारीख को दिल्ली पहुंच रही हैं। अप्रैल के आखिर में भाजपा अध्यक्ष दो दिन के दौरे पर जम्मू जाएंगे।

वीआइपी की सुरक्षा में कटौती नहीं होगी - वेंकैया

नई दिल्ली

वीआइपी को मिली सुरक्षा में कटौती करने की कोई योजना नहीं है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने गुरुवार को दी। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने एंबूलेंस और अग्निशमन वाहनों को छोड़ शेष सभी पर लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। वेंकैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो यह देश के हित में अत्यंत आवश्यक है। इसके तहत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा दी जाती है।

वीआइपी संस्कृति खत्म करने संबंधी सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, हर कोई वीआइपी है और हमारी सरकार का दर्शन यही है। यह हालांकि एक छोटी सी पहल है, लेकिन इससे यही संदेश दिया गया है कि हर किसी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकारें भी लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद कर देंगी। ऐसा नहीं करने पर उसे लोगों की नाराजगी का सामना करना होगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर मंत्री ने कहा कि वर्षों से चले आ रहे इस मामले में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा पर असर के बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने में आपराधिक सांठगांठ का मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ सीबीआइ को मामला चलाने की इजाजत दे दी है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की संवैधानिक प्रतिरक्षा बहाल रहेगी। पद मुक्त होने के बाद उनके खिलाफ मामला चलेगा।